डॉ. चिलूका पूष्पलता
अध्यक्षा-हिन्दी विभाग
दयानंद सागर कॉलेज आँफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स,बैगलुरू
chilukapuspa@gmail.com , 9900524414

भारतीय भाषा माध्यम से व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा : चुनौतियां और संभावनाएं

सार-संक्षेप:
व्यावसायिक शिक्षा दो शब्दों के संयोग से निर्मित है। जिसमें पहला शब्द व्यवसाय एवं दूसरा शब्द शिक्षा है। "व्यवसाय" शब्द जीविकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार के अर्थ में है तथा शिक्षा-संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण युक्त सीखने से है। तात्पर्य-व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय व तकनीकी दो ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के साथ जुड़े हैं। व्यवसाय से आशय वाणिज्य व उद्योग के सम्पूर्ण जटिल क्षेत्र, आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक व निर्माणी उद्योग तथा सहायक सेवाओं के वृहद-जाल वितरण, बैंकिंग आदि से है। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का अंग है। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था उसके व्यायसायिक विकास पर निर्भर करती है। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें।

प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अंग है। व्यासायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से सम्बन्धित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। विज्ञान के विश्वकोष के अनुसार इसका अर्थ है- "व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत उस सब प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है।"

शब्दकुंज: तकनीकी, वाणिज्य, प्राविधिक व निर्माणी उद्योग, प्राविधिक शिक्षा, विश्वकोष, प्रशिक्षण ।

भूमिका:
भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत में उच्च शिक्षा ने स्वतंत्रता के बाद से अभूतपूर्व विस्तार का अनुभव किया है। भारत ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रबंधकों का उत्पादन किया है जिनकी दुनिया भर में बहुत मांग है। अब यह हमारी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता में शीर्ष दस देशों में से एक है, क्योंकि उच्च शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति और उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण। भारत पहले ही ज्ञान विस्फोट के युग में प्रवेश कर चुका है। इसने परमाणु और अंतरिक्ष डोमेन में अपने प्रदर्शन से अपनी जबरदस्त क्षमता साबित की है। आने वाले कुछ दशकों में अंतरिक्ष यान, उपग्रहों, इंटरनेट और वैज्ञानिक जांच के अन्य पहलुओं द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सामने आने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर प्रतिबिंबित करने के अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए विशेष ज्ञान और कुशल व्यक्ति प्रदान करती है। अगले कुछ दशकों में, भारत में युवाओं

का दुनिया का सबसे बड़ा समूह होगा। उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सामने आने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर प्रतिबिंबित करने के अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए विशेष ज्ञान और कुशल व्यक्ति प्रदान करती है। अगले कुछ दशकों में, भारत में युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा समूह होगा। जबकि लोगों और उच्च शिक्षा के बीच संबंध मानक के अनुरूप नहीं है। बढ़ती युवा आबादी क्या हो सकती है?
यदि संभावित रोजगार क्षमता को फलीभूत किया जाता है तो महान संपत्ति। इसके विपरीत, यदि हम शिक्षा और रोजगार प्रदान करने में विफल रहते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक द्वार खोल देगा। स्थिरता प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक आवश्यक उपकरण है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने एक बयान के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन किया- एक राष्ट्र का घनत्व उसके कक्षा कक्षों में आकार दिया जाता है। शिक्षा मानव पूंजी का निर्माण करती है जो आर्थिक प्रगति का मूल है और मानती है कि मानव पूंजी द्वारा उत्पन्न बाहरीताएं आत्मनिर्भर आर्थिक प्रक्रिया का स्रोत हैं।
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति:

State of Higher education in India is in between good and bad. I mean in a nutshell to say neither it is good nor it is that bad. So in this paragraph we shall talk about number of universities,colleges,number of teachers & professors and students enrolled.
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छे और बुरे के बीच है। संक्षेप में मेरा मतलब है कि न तो यह अच्छा है और न ही यह बुरा है। तो इस पैराग्राफ में हम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों और प्रोफेसरों की संख्या और नामांकित छात्रों की संख्या के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2014 में भारत में 670 से अधिक विश्वविद्यालय, कम से कम 38,000 कॉलेज, 817000 प्रोफेसर और शिक्षक और 28000,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या में साल-दर-साल वृद्धि हो रही है। अलग-अलग छात्र अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करते हैं। जैसे कि पूरे देश में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 14,000,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। स्नातकोत्तर के लिए 20490000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। अनुसंधान के लिए लगभग 1370000 और फोरडिप्लोमा के लिए वर्ष 2014 में 1710000 से अधिक छात्रों ने दाखिला लिया। अब हमें बजट मुद्दे पर भी गौर करना चाहिए। भारत सरकार शिक्षा के लिए कितना आवंटन कर रही है? वर्ष 2014 में भारत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। यह राशि 2013 में पिछली बार की तुलना में 17% अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग ने 16,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं जो पिछले साल से 20% अधिक है। इसी तरह सरकार ने इस साल आईआईटी के लिए 24,00 करोड़ रुपये, एनआईटी के लिए 1300 करोड़ रुपये और आईआईएम के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो यह उच्च शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है।
भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। देश मे अब तक दशको पुरानी शिक्षा नीति लागू थी जिससे देश मे शिक्षा का स्तर मे सुधार नहीं हो रहा था।

चुनौतियां और मुद्दे:
आजादी के बाद से हम एक अच्छी और मजबूत शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विभिन्न सरकारों ने प्रणाली में नई और प्रभावी शिक्षा नीतियों को स्थापित करने की कोशिश की लेकिन वे हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अभी भी भारतीयों को हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार मानती है कि नया वैश्विक परिदृश्य उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए बेजोड़ चुनौतियां पेश करता है। यूजीसी ने कहा कि वाणिज्य, मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के स्नातकों के साथ-साथ आतिथ्य, पर्यटन, कृषि, कानून, प्रबंधन, चिकित्सा या इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न व्यावसायिक विषयों से कौशल की एक पूरी श्रृंखला की मांग की जाएगी। इनमें अपर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएं, शैक्षिक क्षेत्र में रिक्त सीटें और उनके खराब संकाय, कम छात्र नामांकन दर, पुरानी और पुरानी शिक्षण पद्धतियां, अनुसंधान मानकों में गिरावट, अप्रेरित छात्र, भीड़भाड़ और छोटी कक्षाएं और व्यापक भौगोलिक, आय, लिंग और जातीय असंतुलन शामिल हैं। बिगड़ते मानकों और सुविधाओं की कमी से संबंधित इन चिंताओं के अलावा, कई निजी शिक्षा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के शोषण की सूचना मिली है। लेकिन भाषा का कोई भी विषय पूर्ण रूप से चित्रित नहीं है।

क्षेत्रीय भाषा में उच्च शिक्षा के सकारात्मक पहलू:

विषय-विशिष्ट सुधार: भारत और अन्य एशियाई देशों में किये गए कई अध्ययन यह बताते हैं अंग्रेज़ी माध्यम के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों के अधिगम प्रतिफलों (learning outcomes) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से विज्ञान और गणित विषय के मामले में अंग्रेज़ी की तुलना में अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों में बेहतर प्रदर्शन स्तर पाया गया है।

भागीदारी की उच्च दर: मातृभाषा में अध्ययन का अवसर उच्च उपस्थिति दर, प्रेरणा और छात्रों में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकने के आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे परिणाम देता है। इसके साथ ही, मातृभाषा से परिचय के कारण माता-पिता की संलग्नता और सहयोग में भी सुधार की स्थिति बनती है। कई शिक्षाविदों द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में ड्रॉपआउट दरों के साथ-साथ कुछ छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये अंग्रेज़ी पर खराब पकड़ को प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है।

कम-सुविधासंपन्न लोगों के लिये अतिरिक्त लाभ: यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिये प्रासंगिक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं (अर्थात अपनी समग्र पीढ़ी में पहली बार स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने वाले) या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं—जो अंग्रेज़ी जैसी किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणाओं से भय महसूस कर सकते हैं।

सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि: यह अधिकाधिक छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio- GER) की वृद्धि करेगा।

भाषाई विविधता को प्रोत्साहन: यह सभी भारतीय भाषाओं की क्षमता, उपयोग और जीवंतता को भी बढ़ावा देगा।इस प्रकार, निजी संस्थान भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/अथवा द्विभाषी कार्यक्रम पेश करने के लिये प्रेरित होंगे। यह भाषा-आधारित भेदभाव को रोकने में भी मदद करेगा।

संबद्ध चुनौतियाँ

नियुक्ति प्रतिमान में परिवर्तन: तृतीयक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने का निर्णय प्रमुख संस्थानों के भर्ती/नियुक्ति निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा क्योंकि वे विषय-वस्तु विशेषज्ञता के विपरीत भाषा प्रवीणता को प्राथमिक मानदंड के रूप में देखने को विवश होंगे। उन्हें शिक्षण के लिये वैश्विक प्रतिभा पूल से शिक्षकों की तलाश करने का अभ्यास भी छोड़ना होगा।

अखिल भारतीय प्रवेश लेने वाले संस्थानों के लिये निरर्थक उपक्रम: ऐसे परिदृश्य में क्षेत्रीय भाषा पर बल देना सार्थक नहीं होगा जहाँ IITs जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान देश भर के प्रवेशकों को आमंत्रित करते हैं।क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता: एक अन्य चुनौती पाठ्यपुस्तकों और विद्वत साहित्य जैसी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की होगी। इसके साथ ही, अर्थ संबंधी अनियमितताओं को दूर रखने के लिये इनके अनुवादों का गुणवत्ता नियंत्रण भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

नियोजन से संबद्ध चुनौती: कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ प्रवेश स्तर के पदों के लिये 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) के स्कोर स्वीकार करती हैं, जो अंग्रेज़ी माध्यम में आयोजित किया जाता है।कॉलेज-शिक्षित व्यक्तियों की पहले से ही निराशाजनक रोज़गार स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन रोज़गार के अवसरों को और बाधित कर सकता है।

संकाय की उपलब्धता: चूँकि भारत में उच्च शिक्षा के अंग्रेज़ी माध्यम की विरासत रही है, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करने के इच्छुक और क्षमतावान गुणवत्तायुक्त शिक्षकों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

वैश्विक मानकों के साथ गति बनाए रखना: क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम देने से छात्रों को वैश्विक श्रम और शिक्षा बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा कर सकने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि निश्चय ही वहाँ अंग्रेज़ी में प्रवणता एक अलग बढ़त प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों के लिये अवसरों की कमी NEP, 2020 के उद्देश्य (अभिजात वर्ग और शेष के बीच की खाई को पाटना) के प्रतिकूल साबित हो सकती है।

यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध है।

आगे की राह

आधार का निर्माण: क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिये सरकार ने जिस तरह की आधिकारिक आज्ञा को अपनाया है, वह समस्याग्रस्त है।

उदाहरण के लिये, अनुदान के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये पहले एक आधार के निर्माण की आवश्यकता है।

IITI को योजना में शामिल करना: सर्वप्रथम अनुवाद और व्याख्या में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का सृजन कर भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त अधिगम और प्रिंट सामग्री का विकास करना होगा। इस संबंध में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (IITI)' की स्थापना की जाएगी जो भारतीय भाषाओं के विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा।

शिक्षा के लिये निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली: सरकार को निष्पक्षता और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित न्यायसंगत प्रणाली विकसित करने के लिये कार्य करना होगा।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि छात्रों की व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी तरह से उनकी पूर्ण शैक्षणिक क्षमता को साकार करने में बाधा न बनें।

इसके साथ-साथ, मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित करते हुए, सरकार को शिक्षा का एक आधारभूत न्यूनतम मानक भी तय करना चाहिये जो सभी असमानताओं को समाप्त करता हो।"क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी के योग" की धारणा को अपनाना: जबकि शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है, छात्रों के लिये अंग्रेज़ी भाषा पर अच्छी पकड़ का होना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि वे 21वीं सदी में वैश्विक मूल-निवासी होने की स्थिति रखते हैं।भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी की पूरकता प्रदान की जानी चाहिये।

'डिजिटल डिवाइड' को भरना: AICTE ने हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है जो अंग्रेज़ी के कंटेंट का 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन अनुवाद करता है।

अपने सभी छात्रों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के स्कूली तथा कॉलेज जाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं इंटरनेट सुविधाएँ प्रदान करने को प्राथमिकता देना होगा।

निष्कर्ष:

भारतीय भाषाएँ शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिये अति आवश्यक हैं क्योंकि वे शिक्षा में समानता को सशक्त करती हैं तथा वे छात्रों को भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उपयोग करते हुए एक स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक समाज में रहने के लिये तैयार करेंगी।

एक तेज़ी से वैश्वीकृत होती दुनिया में देशी भाषा में शिक्षण के निहितार्थ के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। "मातृभाषा बनाम अंग्रेज़ी" से "मातृभाषा और अंग्रेज़ी के योग" की ओर संक्रमण या स्थानांतरण आवश्यक है।

संदर्भ सूची:

- https://www.scotbuzz.org/2019/05/bhasha-kaushal-ka-ar.html
- Kendriya Shikshak Patrta Pariksha Samajik Adhyayan
- JTET JHARKHAND SHIKSHAK PATRATA PAREEKSHA PAPER